Special Issue
“(Global Partnership: India's Collaboration Initiatives for Economic and Social Growth)”

सार्वजनिक उपकमों का निजीकरण में परिवर्तन, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उचित या अनुचित–एक विश्लेषण

Dr. Madan Mohan Varshney[1*] and Vikas Baboo[2]

[1] Assistant Professor & HOD, Department of Commerce, D. R. A. Govt. P. G. College, M. J. P. Rohilkhand University, Bareilly, Uttar Pradesh, India

[2] Research Scholar, D. R. A. Govt. P. G. College, M. J. P. Rohilkhand University, Bareilly, Uttar Pradesh, India

Correspondence Author: Dr. Madan Mohan Varshney

सारांश

वर्तमान समय में प्रत्येक देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विकास है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण तथा उनके कारणों एवं प्रभावों की सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा करता हैं। हो गया भारत एक विकासशील देश है, जहॉ मिश्रित अर्थव्यवस्था पायी जाती हैं। स्वतन्त्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका कम थी। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में मात्र पॉच सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम थे जिनका कुल निवेश 29 करोड रुपये था जोकि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा सामाजिक–आर्थिक कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करना देश के तेज आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण के लिए जरुरी आधारभूत ढांचा पैदा करनें,रोजगार के अवसरों एवं आर्थिक कल्याण और संतुलित क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। परन्तु सार्वजनिक क्षेत्रों का स्वामित्व निजी क्षेत्रों को हस्तान्तिरित करने के पीछे सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकमों का लगातार घाटे में जाना,क्षमता के उपयोग का स्तरहीन होना कर्मचारियों की भरमार, बढता हुआ राजकोषीय घाटा, बढता भ्रष्टाचार ,नौकरशाही भाई–भतीजावाद फिजूलखर्ची को रोकने एवं नियन्त्रण करने के लिए आवश्यक था।निजीकरण की उचित प्रकिया देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है जहॉ उसके फायदे है वहीं गंभीर नुकसान भी है यहॉ तक कहा गया है कि निजी कम्पनियां बडे व्यापारिक सौदों को निपटाने के लिए सरकारी कार्यालयों को मोटी रिश्वत देती हैं।

मूलशब्द: सार्वजनिक क्षेत्र, निजीकरण, विनिवेश नीति, निजीकरण के पश्चात प्रदर्शन, आर्थिक कल्याण एवं विकास, दक्षता एवं कुशलता, राजकोषीय घाटा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वैधानिक संगठन,लाभ अधिकतमकरण, प्रतिस्पर्धा जवाबदेही।

परिचय

प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रों के स्वामित्व का हस्तान्तरण निजी हाथों में ,निजीकरण की आवश्यकता एवं इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करता है। भारत जैसे विकासशील देश के आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र अति आवश्यक है।भारत में निजीकरण की शुरूआत तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हॉ राव एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ0 मनमोहन सिंह द्वारा सन 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाकर देश में निजीकरण की नींव रखी।इसी नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उपकमों की संख्या को 17 से घटाकर 8, फिर 6 और अब 3 कर दिया गया हैं। सार्वजनिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का वह अंश है जिनका संचालन राज्य के स्वामित्व वाले उपकमों द्वारा किया जा रहा हैं। लेकिन सार्वजनिक उपकमों का निजीकरण वर्तमान समय की मॉग है और देश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक भी हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों की अक्षमता और,उत्पादकता में कमी बढता राजस्व घाटा निरन्तर घाटे में या बीमार उद्योगों का जीर्णोधार एवं लागतों में कमी करने के लिए निजीकरण की जरूरत पडी।निजीकरण शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है–निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम ,औद्योगिक संस्थान और इकाईयों का स्वामित्व का हस्तान्तरण निजी क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। भारत में निजीकरण का इतिहास उतार चढाव वाला रहा है,यह असुविधा और संदेह की प्रतिकियाओं को दर्शाता है।विनिवेश पर 1993 की रिपोर्ट में सी0 रंगराजन समिति ने आकमक सिफारिश की,जिसमें कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों में हिस्सेदारी की 100 प्रतिशत बिकी भी शामिल थी। 1991 से अब तक विभिन्न क्षेत्रों में समय दर समय निजीकरण किया गया वर्ष 1997 में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 11 कंपनियां जो लाभ की स्थिति में थी उन्है नवरत्न का दर्जा दिया ।

सार्वजनिक क्षेत्र क्या हैं

सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम एक वाणिज्यिक इकाई या एक कंपनी से सम्बन्धित है जिन पर पूर्ण या आंशिक रूप से स्थानीय,राज्य या देश की सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार द्वारा ही उनका प्रबन्ध किया जाता है।उपकम शब्द को प्राचीन माना जाता है अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो एक पी0सी0यू0 एक सरकार है।

सार्वजनिक क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में कुछ बडे सार्वजनिक उपकमों जैसे– बीएसएनएल, एमटीएनएल और एयर इण्डिया में घाटे की स्थिति लगातार बढ रही है,इन उपकमों का घाटा इनके राजस्व प्राप्ति से अधिक है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकमों को तीन भागों भागों में वर्गीकरण किया है–केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम,सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ,राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम। जनवरी 2023 तक 12 महारत्न, 13 नवरत्न

एवं 62 मिनीरत्न कंपनियां है।सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ सामान्य श्रेणियां निम्नवत प्रकार है–

महारत्न कंपनी

महारत्न योजना मई 2010 में शुरू की गई थी।महारत्न कंपनी के लिए पहले वह नवरत्न कंपनी हो और सेबी के अन्तर्गत न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहिए। औसत वार्षिक व्यवसाय 25,000 करोड से अधिक और पिछले तीन वर्षो की अवधि में औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड रूपये से अधिक एवं पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड रूपये से अधिक होने के साथ–साथ कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में इंटरनेशनल बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए।

Fig 1

नवरत्न कंपनी

नवरत्न कंपनी का मूलरूप 1997 में भारत सरकार द्वारा लाया गया।किसी भी कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसे मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। नवरत्न कंपनियां भी बडे उद्यम है लेकिन महारत्न कंपनियों की तुलना की अपेक्षा में छोटी है। का अधिकार क्षेत्र अधिक स्वायत्तता दी गयी जिससे देश की कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्राप्त हो सके ।

मिनीरत्न

मिनीरत्न योजना की शुरूआत वर्ष 1997 में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्द्धी बनाने और लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान करने के नीतिगत उद्धेश्य के अनुसरण में की गई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र की तीसरी श्रेणी है,जो आकार में छोटी है जिसकी वित्तीय और परिचालन शक्तियॉ महारत्न एवं नवरत्न की अपेक्षा कम होती है।मिनीरत्न की दो श्रेणियां है–श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2।मिनीरत्न श्रेणी 1 में कंपनी ने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो तथा तीन साल में एक बार कम से कम 30 करोड रूपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो।मिनीरत्न श्रेणी 2 में सीपीएसई द्वारा पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ अर्जित किया हो और उसकी निवल संपत्ति सकारात्मक हो।

Fig 2

सार्वजनिक उपकमों का निजीकरण या विनिवेश करने की आवश्यकता क्यों पडी

सरकार को निजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के पीछे आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था बदहाल थी और देश की प्रति व्यक्ति आय तथा नेशनल इनकम को बढाना था।जिसके द्वारा लोगों के जीवन स्तर में सुधार,बेरोजगारी दर में कमीं और देश की आर्थिक क्रियाओं का विकास किया जा सकें।निजीकरण का एक और महत्वपूर्ण कारण सार्वजनिक क्षेत्रों की कम्पनियों का खराब प्रदर्शन,सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का घाटे में चलना आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों,कार्य के प्रति निरंकुशता और राजनैतिक हस्तक्षेप निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया से परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण न कर पाना। इन विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए 1991 में सरकार द्वारा उदारीकरण,निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया गया था। निजीकरण के संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री पी0 वी नरसिम्हा राव ने कहा था।अगर हमें भारत के शरीर को कपडें से ढकना,तो सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की मदद की भी जरूरत है। हमें विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मुद्रा स्फीति से उबारने के लिए निजीकरण ही

सर्वोत्तम समाधान है। **तिरूवल्लुवर** का कथन है–**एक राजा वह है जो अपने राज्य की आय संजोता हैं,संचय करता है,रक्षा करता है तथा विधिवत व्यय करता है।** एक सिक्के के दो पहलू होते है इसी प्रकार निजीकरण के भी अपने दुष्प्रभाव है।उन दुष्प्रभावों को देखकर हम देश के आर्थिक विकास के लिए ।

निजीकरण

निजीकरण से आशय उस स्थिति से है जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रबन्धन,नियन्त्रण एवं स्वामित्व निजी क्षेत्रों को स्थानान्तरित कर देती है और सरकार स्वयं उसके स्वामित्व से भार मुक्त हो जाती है,यह अक्सर अनुबन्ध के माध्यम से किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में परिवर्तित करने के दो तरीके हैं,जैसे–

- **स्वामित्व का हस्तान्तरण**–सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व प्रबन्धन और नियन्त्रण का हस्तान्तरण पूर्ण रूप से अथवा 50 प्रतिशत से अधिक भाग निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित करने से है।
- **विनिवेश**–विनिवेश से तात्पर्य सरकार द्वारा की जाने वाली सम्पत्तियों के विक्रय से है।सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को बेचकर विनिवेश के रूप में निजीकरण कर देती है इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी रहती है लेकिन सरकार स्वामित्व अपने पास रखती है। एशिया की सबसे बडी ब्रेड निर्माता कंपनी मॉडर्न फूडस निजीकरण होने वाली पहली केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी बन गयी थी।

Fig 3

निजीकरण के उद्धेश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था में निजीकरण के निम्न उद्देश्य हैं–

- निजीकरण द्वारा आर्थिक विकास के लिए संसाधनों को एकत्रित करना एवं उनका कुशलतम प्रयोग करना।
- निजी क्षेत्र की प्रबन्धकीय कार्यकुशलता एवं दक्षता का प्रयोग करना।
- निजीकरण का मुख्य उद्देश्य बाह्य ऋणों में कमी करना।
- नए–नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना कर आयात प्रतिस्थापन प्रक्रिया को सबल बनाना।
- निजीकरण द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में वृद्धि करना और परिचालन क्षमता को बढ़ाना।
- निजी क्षेत्र की उत्पादन क्रियाओं को आवश्यकता अनुसार एवं प्राथमिकता के अनुरूप सार्वजनिक क्षेत्र के साथ समन्वित करना।
- निजीकरण द्वारा तकनीकी का प्रसार करना और अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकरण में परिवर्तित करना।
- उपक्रमों एवं औद्योगिकीकरण में विवेकीकरण के लिए आर्थिक अनुसन्धान एवं विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन करना।
- निजीकरण द्वारा राजकोषीय घाटे को कम करना और गैर विकास व्ययों की रोकथाम करना।
- निजीकरण द्वारा पूँजी की वृद्धि की तुलना में उत्पादन में कम वृद्धि पर रोक करना।

विनिवेश

विनिवेश से तात्पर्य सरकार द्वारा की जाने वाली सम्पत्तियों के विक्रय से है। सरकारी सम्पत्तियों में सामान्यतया केन्द्र और राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा अचल सम्पत्तियों को सम्मिलित किया जाता है। विनिवेश में कोई स्वामित्त्व हस्तान्तरित नहीं किया जाता बल्कि इसका उद्देश्य संगठन के प्रदर्शन में वृद्धि करना होता है। प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। सन् 1991–92 में विनिवेश द्वारा 2500 करोड़ रूपये जुटाने का लक्ष्य प्रस्तावित किया। सरकार उस लक्ष्य से 3040 करोड़ रूपये अधिक जुटाने में सफल रही। सन् 2017–18 में लक्ष्य लगभग 1,00,000 करोड़ रूपये के विनिवेश का था लेकिन उसकी उपलब्धि लगभग 1,00,057 करोड़ की रही। वर्ष 2014 के बाद से सरकार ने विनिवेश लक्ष्यों को दो बार जुटा पाई है जिसमें वर्ष 2017–18 में सरकार ने 72500 करोड़ के मुकाबले 1,00,000 करोड़ और 2018–19 में 80000 करोड़ के मुकाबले 94700 करोड़ विनिवेश लक्ष्य की प्राप्ति की है। विनिवेश एक ऐसी तकनीक है जो सरकारी खजाने पर राजकोषीय बोझ को कम करने और विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त जुटाने के लिए किया जाता है। साधारण विनिवेश के विपरीत रणनीतिक विक्री या विनिवेश से तात्पर्य एक प्रकार के निजीकरण के पर्याय रूपी है। विनिवेश प्रक्रिया का संचालन निवेश और सार्वजनिक सम्पत्ति प्रबन्धन विभाग क्प्ब्।ड ;क्मचंतजउमदज वि प्दअमेजउमदज ंदक च्नइसपब ।मजे डंदंहमउमदजद्ध के द्वारा किया जाता है जोकि वित्त मंत्रालय के अधीन आता है।

विनिवश विधि

अल्पांश विनिवेश – इस विधि में सरकार कम्पनी में बहुमत रखती है, प्रायः 51 प्रतिशत से अधिक अंश अपने पास रखती है, ताकि प्रबन्धन नियन्त्रण सुनिश्चित हो सके।

बहुमत विनिवेश – सरकार अधिग्रहण करने वाली इकाई का नियन्त्रण देती इसके अतिरिक्त कुछ हिस्सेदारी को बरकरार रखती है।

पूर्ण निजीकरण – कम्पनी का 100 प्रतिशत नियन्त्रण खरीददार को सौंप दिया जाता ळे।

विनिवेश की आवश्यकता एवं उद्धेश्य

- विनिवेश के द्वारा सरकार को राजकोषीय घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- विनिवेश ने आर्थिक संसाधनों को जुटाकर बड़े स्तर पर बुनियादी ढाँचे के विकास को मजबूत बनाया है।
- सरकार के कर्ज को विनिवेश द्वारा कम किया गया जोकि केन्द्र के राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण और ब्याज का भुगतान करने में जाता।
- विनिवेश प्रक्रिया के द्वारा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य स्वच्छ भारत से सम्बन्धित कई सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया गया।
- विनिवेश के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि हुई है और देश के उत्पादन स्तर में भी वृद्धि हुई है।
- विनिवेश नीति द्वारा सार्वजनिक उपक्रम जो लगातार नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हो रहा ऐसे उपक्रमों को विनिवेश द्वारा निजी क्षेत्रों को हस्तान्तरित किये गए।
- सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 का विनिवेश लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रूपये रखा है।

विनिवेश नीति के उद्देश्य

- सरकारी बीमार कम्पनी और दिवालिया हो रहे सार्वजनिक उपक्रमों पर आर्थिक बोझ का कम करना।
- विनिवेश ने निजी स्वामित्व और सरकारी सम्पत्तियों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना।
- विनिवेश द्वारा शोध एवं विकास, कार्यबल का युक्तिकरण और

पुनः प्रशिक्षण पर जोर देना।
- विनिवेश द्वारा बाजार प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता और नए उपक्रमों की प्रोत्साहित करना।

साहित्य समीक्षा

- **सोहन्त्रे एवं विनोद मिश्रा 1991**– सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश नीति एक प्रतिकूल कदम पर अपने लेख में कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी को दूर करने के लिए आर्थिक रणनीति बनाई गयी लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों की बेहतरी विनिवेश के पैसे का उपयोग देश के बुनियादी ढॉचे के विकास में करना।
- **शंकर एवं मिश्रा 1994** – अपने लेख सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश में वर्णन किया है कि जब देश संकट में था तब आर्थिक आपदाएं और बाहरी आर्थिक समुदाय द्वारा दिवालियापन के खतरें का सामना करते हुए,भारतीय सरकार ने विनिवेश का समर्थन किया।सार्वजनिक क्षेत्रों की अक्षमता लगातार बढता घाटा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहें।
- **अनुराग 2007** – सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का विनिवेश पर अपनें शोध में विनिवेश के प्रति भारतीय परिपेक्ष्य की जॉच की और कहा 1990 के दशक में सुधार प्रक्रिया होने के बाद विनिवेश िपूरी तरह से गलत हो गया ।शोध में पाया गया कि 1991 से 2001 के दशक के लिए विनिवेश उत्साहवर्धक नही रहा क्योंकि निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले आय प्राप्त न हो पायी थी।
- **आशीश श्रीवास्तव 2014** – अपने लेख भारत में विनिवेश; एक प्रायोगिक अध्ययन में पाया गया विनिवेश देश के लिए अच्छा है जोकि देश की अर्थव्यवस्था सरकार को राजस्व प्रदान करती है।उनका सुझाव है कि सरकार को समय समय पर नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए एवं लक्ष्य तय करने के बाद विनिवेश उसके मुताविक और विनिवेश प्रकिया को पारदर्शी होनी चाहिए।

अध्ययन के उद्धेश्य

वर्तमान अध्ययन निम्नलिखित उद्धेश्यों को प्राप्त करने के लिए आयोजित किया गया हैं–
- सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी दक्षता में सुधार के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जा रही है।
- निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के विस्तार में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए के प्रोत्साहित किया जाता है।
- सरकार पर वित्तीय बोझ, असफल और अप्रभावी सार्वजनिक उपक्रमों से हिस्सेदारी वापिस लेना।

अनुसंधान किया विधि

प्रस्तुत अध्ययन वर्णानात्मक है जो कि द्वितीय आंकड़ों पर आधारित है अध्ययन के लिए आवश्यक द्वितीयक समंक प्रकाशित प्रतिवेदनों से एकत्रित किया गया है। दीपम, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, वेब साइटों आदि स्रोतों के माध्यम से लिया गया है शोध में पी.एस.यू. से सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण बढ़ते राजकोषीय घाटे का कारण बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास का वित्त पोषण करना है।

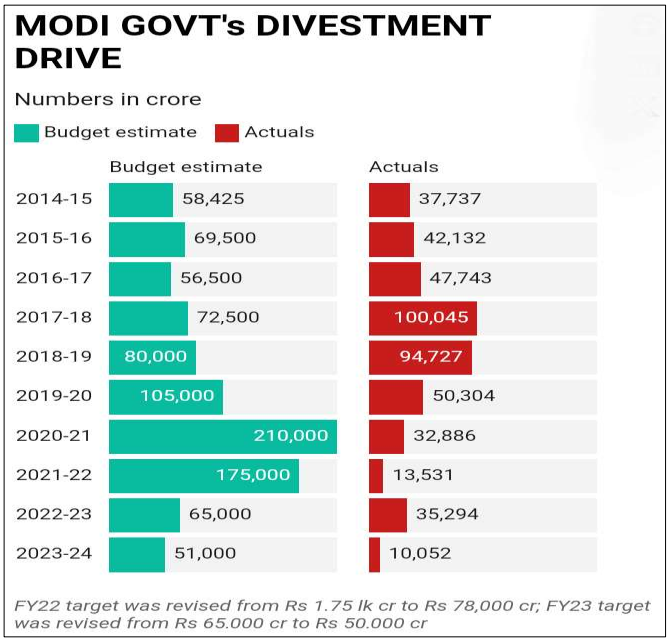

Fig 4

सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण एवं विनिवेश

सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश का मतलब होता है सरकारी उद्यमों या सेवाओं में निवेश करना या उन्हें निजी स्वामित्व में लेना। यह एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें सरकारी संस्थानों या सेवाओं को निजी सेक्टर के लिए खुला किया जाता है या उन्हें निजी निवेशकों के लिए उपलब्ध किया जाता है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र में नए निजी उद्यम बनते हैं और सरकारी निवेशकों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है।

कुछ प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश शामिल हो सकता है–

- परिवहन, सरकारी हवाईअड्डे, रेलवे, और सड़क परिवहन सेवाएं
- निजी स्वामित्व में ली जा सकती हैं या नए निजी परिवहन सेवाओं के लिए निवेश किया जा सकता है।
- ऊर्जा, बिजली उत्पादन, ऊर्जा यातायात, और ऊर्जा संग्रहण क्षेत्रों में सरकारी निवेश को निजी स्वामित्व में बदला जा सकता है।
- उद्यमिता और उद्योग,सरकारी उद्योगों और संगठनों को निजी स्वामित्व में बदला जा सकता है या नए निजी उद्यमों के लिए निवेश किया जा सकता है।
- बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, सरकारी बैंकों को निजी स्वामित्व में बदलने या नए निजी बैंकों की शुरुआत के माध्यम से सार्वजनिक वित्तीय सेवाओं में निवेश किया जा सकता है।

- शिक्षा और स्वास्थ्य,सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं निजी स्वामित्व में ली जा सकती हैं या नए निजी विद्यालय और अस्पतालों की शुरुआत के लिए निवेश किया जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और स्वावलंबन को बढ़ावा देना है, जिससे सेवाएं अधिक अद्यतित, कुशल, और दक्ष बन सकती हैं।

सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण में विनिवेश

- सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें सरकारी उद्यम या सेवाएं निजी स्वामित्व में ली जाती हैं या निजी सेक्टर के निवेशकों के लिए खुली जाती हैं। इसका मतलब होता है कि सरकारी संस्थान या सेवाएं निजी निवेशकों के द्वारा संचालित की जाती हैं और सरकार इसमें अपना सीधा या अप्रत्यक्ष निर्देश नहीं करती है।
- सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण में विनिवेश का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि निजी निवेशक संस्थानिक कुशलता, अधिकतम उत्पादकता, के साथ संचालित करने की क्षमता रख सकते हैं।
- इसके माध्यम से सरकार स्वामित्व में रहने वाले उद्यमों को बढ़ावा देती है और आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है।

सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण में विनिवेश के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं–

- निजी विमुक्त गैस प्रयोगशाला, सरकार द्वारा संचालित गैस प्रयोगशाला जो पहले सार्वजनिक सेक्टर में थी, उसे निजी स्वामित्व में लिया गया है।
- निजी बैंकों का संचालन, सरकारी बैंकों को निजी स्वामित्व में बदला जा सकता है या नए निजी बैंकों को शुरुआत के लिए निवेश किया जा सकता है।
- निजी विमानन कंपनियां जोकि सार्वजनिक सेक्टर में संचालित होने वाली विमानन कंपनियां निजी स्वामित्व में ली जा सकती हैं या नए निजी विमानन कंपनियों के लिए निवेश किया जा सकता है।

निष्कर्ष

परिणामतः सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जिसे सार्वजनिक क्षेत्र इकाई भी कहा जाता है अनिवार्य रूप से केन्द्र, क्षेत्रीय या राज्य सरकार के अधीन उद्यमों के लिए स्थापित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021 में इकॉनामिक टाइम्स में छपे लेख के अनुसार सरकार के मुताबिक 255 परिचालन इकाईयों में से 177 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मुनाफा बड़ा 31 मार्च 2021 वित्त वर्ष में कुल 24,26,045 करोड़ का कारोबार हुआ जबकि घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्रों का कुल घाटा 29.86 प्रतिशत कम हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र ने न केवल जी.डी.पी. में सहायता की है वृद्धि और विकास एवं आर्थिक कल्याण और आय असमानता से निपटने में सहायता की है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को निजीकरण में परिवर्तित करने के पीछे आर्थिक मंदी, अर्थव्यवस्था का पुर्नगठन सरकारी उद्योगों की अक्षमता एवं बीमार इकाइयों का जीर्णोद्धार मुख्य कारण रहे। भारत वास्तव में निजीकरण करनें में उल्लेखनीय रूप से धीमा रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों पर निजीकरण की जिम्मेदारी डालकर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव किया गया। 1991–99 तक विनिवेष का लक्ष्य 34,300 करोड़ के लक्ष्य में से 16,809 करोड़ का ही लक्ष्य प्राप्त कर पाये जबकि 1999–2004 तक 58,500 करोड़ के लक्ष्य में से 24,619 करोड़ रूपये ही जुटा पाई जबकि 2004–14 तक 1,93000 करोड़ रूपये के लक्ष्यमें से 1,14045 करोड़ रूपये ही जुटा पाये और 2014–2020 तक 4,26,925 करोड़ रूपये में से 3,05,357 करोड़ रूपये की जुटा पाये। सरकार ने अब तक 2022–23 के विनिवेष लक्ष्य 31,106 करोड़ रूपये में से 20,500 करोड़ रूप्ये ही जुटा पायी भारत में विनिवेष से सम्बन्धित निम्न समस्याऐं है जैसे राजनीतिक विरोध, मूल्यांकन का मुद्दा, श्रमिकों का मुद्दा, कानूनी चुनौतियां आदि। भ्रष्टाचार का सम्बन्ध निजी या सार्वजनिक क्षेत्र से नहीं है ये व्यक्ति के नजरिये से है। भारतीय अर्थव्यस्था पर निजीकरण ने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से प्रभाव डाला है। हमें इसे सर्वोत्तम तरीके से लागू करने की विधि खोजने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Privatization
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Public_sector_undertakings_in_India
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Disinvestment_in_India
4. https://www.drishtiias.com/pdf/privatisation-of-pses.pdf
5. https://www.economicsdiscussion.net/india/privatisation-of-the-public-sector-industries-in-india/14194
6. https://www.civilsdaily.com/privatisation-of-public-sector-enterprises-in-india/
7. https://taxguru.in/corporate-law/privatization-public-sector-undertakings-psus.html
8. https://www.mbauniverse.com/group-discussion/topic/business-economy/privatization-of-indian-economy
9. https://www.civilserviceindia.com/current-affairs/articles/privatisation-and-india-economy-growth.html
10. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/cabinet-approves-new-strategic-disinvestment-process/articleshow/71445908.cms?from=mdr.
11. Anurag -- Ph.D Thesis on the topic Disinvestment of PSUs.
12. Gangadhar and Yadgiri -- Disinvestment in PSEs – published in Management and Accounting Research Journal, 2002 Jan-Mar, p31-54.
13. Ashish Srivastava. Disinvestment in India: Am Empirical Study – International Journal of Management. 2014 April;5(4):19-24.
14. DIPAM Report.
15. NITI Aayog Report.
16. Related web sources.